देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवार 31.03.2026
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रही जनगणना के पहले चरण के लिए 33 प्रश्न अधिसूचित किए।
- प्रदेश में आगामी 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जा रहा है।
- नगर निगम देहरादून ने स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों को गति देते हुए शहर की सफाई व्यवस्था की निगरानी और अधिक सख्त की। वार्डवार कार्य योजना तैयार।
- एलपीजी की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए देहरादून जिला प्रशासन का जांच अभियान जारी।

जनगणना / प्रश्न

केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रही जनगणना–2027 के पहले चरण के लिए 33 प्रश्न अधिसूचित किए हैं। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि जनगणना दो चरणों में होगी। पहले चरण में घर–घर जाकर सूचीकरण और स्व–गणना की प्रक्रिया पूरी होगी। यह चरण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार 30 सितंबर तक चलेगा। स्व–गणना पोर्टल 16 भाषाओं में उपलब्ध होगा।

चारधाम स्वास्थ्य सेवा

प्रदेश में आगामी 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारियों में जुटा है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जा रही है। साथ ही यात्रा मार्ग पर अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल मेडिकल यूनिट और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग विशेष रूप से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्वास्थ्य जोखिम को ध्यान में रखते हुए तीर्थयात्रियों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य जांच और जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर हेल्थ स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा रही है, ताकि गंभीर बीमारियों से ग्रसित यात्रियों की समय पर पहचान हो सके। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण

नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद अब पुनर्वास की प्रक्रिया तेज हो गई है। करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर 4 हजार 300 से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने के लिए शिविर लगाए जाने शुरू हो गए हैं। रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में छह स्थानों पर शिविर लगाकर प्रभावित परिवारों की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी जाएगी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है।

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप यह शिविर लगाए जा रहे हैं और नियमों के अनुसार पात्र लोगों को चिन्हित किया जाएगा।

गौरतलब है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में 24 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी, जिसमें प्रभावित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शिविर लगाने के निर्देश दिए गए थे।

देहरादून नगर निगम

नगर निगम देहरादून ने स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों को गति देते हुए शहर की सफाई व्यवस्था की निगरानी और अधिक सख्त कर दी है। नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निगम ने सभी वार्डो का वर्गीकरण करते हुए वार्डवार विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है, जिसके तहत प्रत्येक वार्ड की आवश्यकता और चुनौतियों के अनुसार कार्य किया जायेगा। जिन वार्डों में गैर सरकारी संगठन या कम्पनी द्वारा किए जा रहे कार्यों को संतोषजनक नहीं पाया गया है, उन्हें सख्त चेतावानी देते हुए त्वरित सुधार के निर्देश दिये गये हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण–2026 को लेकर निगम ने सभी मानकों में गुणात्मक सुधार किया है। "सोर्स सेग्रीगेसन" को बढावा देने के लिये नगर निगम द्वारा वार्डवार विशेष अभियान संचालित किए जा रहा हैं। इन अभियानों के माध्यम से गीले और सूखे कचरे को अलग–अलग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा हैं। वहीं, नगर निगम ने वार्डों में गत एक वर्ष में 77 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक डोर–टू–डोर कूड़ा उठाया है, जिसे शीघ्र शत–प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको लेकर संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थओं को निर्देशित किया गया है।

गैस आपूर्ति

देहरादून जिला प्रशासन, एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार जांच अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में उप जिलाधिकारी सदर हरी गिरी के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में जांच की। निरीक्षण के दौरान रिंग रोड क्षेत्र में कई डिलीवरी कर्मी मोटरसाइकिल से सिलेंडर वितरित करते पाए गए, जिनका तेल कंपनियों से कोई वैध अनुबंध नहीं था। इससे गैस की कालाबाजारी की आशंका जताई गई। टीम ने दो गैस एजेसियों के गोदामों का भी निरीक्षण किया, जहां छोटे वाहनों से गैस आपूर्ति किए जाने की पुष्टि हुई। इस पर संबंधित एजेंसियों को अनुबंधित लोडर वाहनों के माध्यम से ही गैस डिलीवरी करने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने बताया कि वर्तमान में 36 हजार 500 से अधिक घरेलू और करीब एक हजार छह सौ इकहत्तर व्यावसायिक सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध है। प्रशासन का कहना है कि मांग को देखते हुए एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति लगातार बढ़ाई जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

नारी निकेतन

राजधानी देहरादून के केदारपुर स्थित नारी निकेतन में एक संवासिनी की आत्महत्या के मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने नारी निकेतन की अधीक्षिका, कर्मचारियों और शव बरामद करने वाली चौकीदार से घटना को लेकर विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, उनकी नियमित निगरानी करने और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने को कहा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। श्रीमती आर्या ने बताया कि मामले की जांच जारी है और अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से अस्वस्थ संवासिनियों की देखभाल के लिए मनोचिकित्सकों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करने को कहा गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।